भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -2517
उत्तर देने की तारीख0-40/82025/

रोजगार पाने की क्षमता संबंधी शैक्षिक पाठ्यक्रम

†2517. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की जानकारी है, जो यह उजागर करती है कि शिक्षित युवाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बाजार में नौकरियों की माँग के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है; और
(घ) औद्योगिक निकायों के साथ सहयोग करके शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): रोज़गार और बेरोज़गारी के आधिकारिक आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टें एमओएसपीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और इन्हें इस लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mospi.gov.in/downloadreports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All

भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शुरू की है। एनईपी का उद्देश्य देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और उसे बेहतर बनाना है, ताकि एक समावेशी, समतामूलक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित की जा सके, जिससे शिक्षार्थियों को भावी चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

एनईपी स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और व्यावहारिक कौशल को शामिल करके मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने पर बल देती है, जिससे व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच बड़ा अंतर समाप्त हो जाता है।

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को अधिसूचित किया है, जिससे शिक्षा जगत में कौशल शिक्षा का एकीकरण संभव हो पाया है। यह इंटर्नशिप और परियोजनाओं के साथ-साथ कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, जैसे विविध क्षेत्रों के माध्यम से क्रेडिट संचयन को भी सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 50% के संचयन का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को छात्रों को बहु-विषयक ज्ञान प्रदान करने और उन्हें उद्योग जगत के लिए तैयार करने में सक्षम बनाया है।

इसके अलावा, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षुता युक्त डिग्री कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं ताकि स्नातकों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें रोजगार दिलाने के उद्देश्य से अपेक्षित अध्ययन के दौरान व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सके।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और छात्रों को उद्योग-संगत ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कई कदम उठाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी), रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या संशोधन समितियों में उद्योग हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

- छात्रों और संकाय सदस्यों की इंटर्नशिप, कौशल विकास और उन्नयन की सुविधा के लिए अग्रणी उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल इंटर्नशिप दिशानिर्देश जारी किए गए। इंटर्नशिप, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई द्वारा जारी किए गए मॉडल पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक है। ये दिशानिर्देश पूर्णकालिक या अंशकालिक इंटर्नशिप प्रदान करते हैं।
- सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच पर्क को सुगम बनाने के लिए एआईसीटीई द्वारा उद्योग शैक्षणिक गतिशील रूपरेखा शुरू की गई, जिससे शिक्षा और उद्योग के बीच सहकार्यता को सुविधाजनक बनाया जा सके।

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों की सहकार्यता से 27 फरवरी 2024 को स्वयम प्लस मंच का विमोचन किया है। यह मंच अग्रणी उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में छात्रों/शिक्षार्थियों को उच्च-गुणवत्तापूर्ण अधिगम और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है, जिससे उन्हें पुनः कौशल प्राप्त करने, कौशल बढ़ाने और रोज़गार के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ 65 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 जुलाई 2025 तक, 16 विभिन्न क्षेत्रों में 400 से अधिक पाठ्यक्रम इस मंच पर उपलब्ध हैं, और 3 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन के लिए नामांकन कराया है।

शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने और उन्हें नौकरी पर प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) लागू की है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, एनएटीएस योजना के तहत 12.94 लाख प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.23 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है।

***